RNI NO. MPHIN/2022/8528
डाक पंजी.क्र. MP/KDW/93/2023-24

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

स्मार्ट किसान की पहली पसन्द
Haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 04 अंक 07 | (प्रति माह) सितंबर | पृष्ठ-8 | मूल्य, 5 रुपये

धराली में आयी इस आपदा का परिदृश्य वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा से मिलता.जुलता है..

उत्तराखंड में आपदा, धराली के बाद अब थराली थर्राया

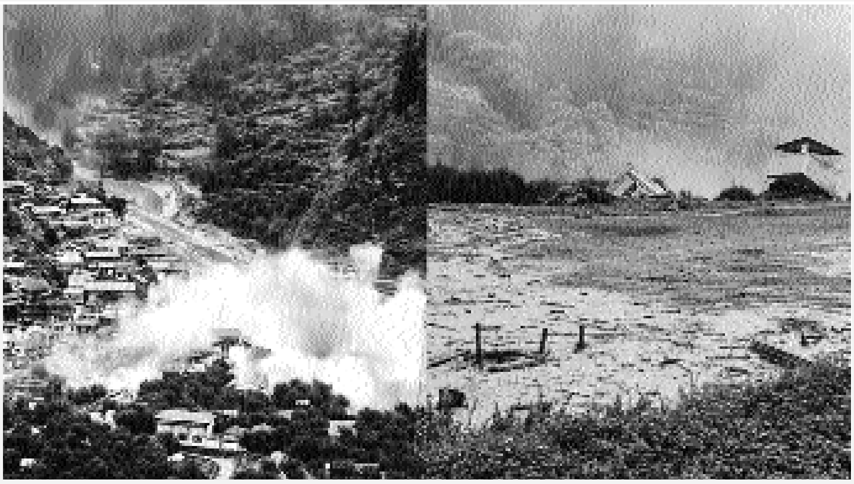

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

उत्तराखंड, देहरादुन। आसमानी बारिश देवभूमि उत्तराखंड में अब हर दिन कहर बरपा रही हैं। धराली की आपदा से उबार भी नहीं था कि थराली और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मच गई। नगर पंचायत थराली, चेपड़ो, सबगड़ा, कुलसारी सहित कई क्षेत्रों में मकानए दुकानें और गौशालाएं मलबे में दब गईं। आपदा में चेपड़ो गांव का एक 78 वर्षीय बुजुर्ग लापता हो गया है, जबकि सबगड़ा गांव में एक 20 वर्षीय युवती की मलबे में दबकर मौत हो गई। चेपड़ो में आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपद उत्तरकाशी में पांच अगस्त को खीर गंगा की भारी बाढ़ ने धराली कस्बे का भूगोल ही बदल दिया है।

हरिद्वार.उत्तरकाशी.गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे धराली पड़ाव में खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों से आये जल सैलाब ने जिस उन्माद के साथ धराली के मकानों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दियाए वह हम सबके लिए विचलित कर देने वाली एक त्रासदी पूर्ण घटना के तौर पर सामने आयी है।

धराली में आयी इस आपदा का परिदृश्य वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा से बहुत कुछ मिलता.जुलता है। देखा जाय तो इस तरह की आपदाएं प्राकृतिक तो होती ही हैं परन्तु हमारी लापरवाही आपदा के परिणामों हुए नुकसान को और बढ़ा देती है।

उत्तरकाशी के धराली के बाद चमोली के थराली में भी एक गदेरे के उफान पर आ जाने से जान.माल का नुकसान हुआ है। गदेरे में पानी के साथ आए मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से रात जागते हुए कट रही हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के प्रभारी निदेशक रोहित थपलियाल ने बताया कि थराली में 22 अगस्त से 23 अगस्त की सुबह तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। धराली में स्थित ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन पर 147मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। यह बहुत भारी बारिश के श्रेणी में आता है।

हालांकि वह यह साफकर देते हैं कि यह अतिवृष्टि यानी बादल फटने की श्रेणी में नहीं आता।

23.24 की रात तहसील करीब एक बजे थराली के टुनरी गदेरे में पानी बढ़ने के कारण तहसील परिसर, चेपड़ो गांव के बाजार, कोटदीप बाजार और कुछ घरों में 1 से 2 फीट मलबा घुस गया और कुछ वाहन भी मलबे में दब गए। ग्राम संगवाड़ा में एक मकान में मलबा आने के कारण एक युवती की मलबे में दबने से मौत हो गई, जिसका शव डीडीआरएफ थराली के जवानों ने मलबे से बरामद कर लिया है।

इसके अलावा एक व्यक्ति लापता भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है और दो दर्जन से अधिक लोगों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया है।

चमोली जिला प्रशासन के अनुसार जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर राहत.बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीमें राहत बचाव का कार्य कर रही हैं।

बीआरओ, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है। राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और शहीद भवानीदत्त इंटर कॉलेज चेपड़ो में रिलीफसेंटर बनाया गया है। साथ ही लोगों को रिलीफ सेंटर तक लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गयी है।

भारी बारिश की चेतावनी के चलते शनिवार को थरालीए देवाल व नारायणबगड़ विकासखंड के स्कूल बंद रखे गए।

नारायण बगड़ के रहने वाले प्रकाश नेगी ने डाउन टू अर्थ से कहा कि थराली, देवाल और नारायण बगड़ गांवों में 23 अगस्त को बहुत ज्यादा बारिश हुई है। वह कहते हैं कि बारिश से पिंडर नदी ही नहीं, गदेरे भी उफान पर हैं। नदी और गदेरो को उफनता देखकर लोगों ने रात जागकर काटी।

नेगी यह भी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से थराली में लगातार फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। दो साल पहले प्राणमती गदेरे में एक साल में 2 बार फ्लैश फ्लड आया था।

21 अगस्त को बड़कोट तहसील के स्यानाचट्टी में गदेरे में मलवा आने से बनी अस्थाई झील का पानी कम होने लगा है और स्थिति सामान्य होने लगी है। बता दें कि स्यानाचट्टी के कुपड़ा खड्ड में मलबा बोल्डर आने के कारण यमुना नदी में बनी झील बन गई थी। प्रशासन के लिए इसे खोलना बड़ी चुनौती बन हुआ था क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे थे।

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि गुरुवार रात बारिश से पानी बढ़ गया था और लगातार मलबा गिरने की वजह से पोकलैंड मशीनें वहां काम नहीं कर पा रही थीं।

इसके बाद झील को पंक्चर करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया और रात से झील से पानी निकलना शुरू हो गया।

शनिवार को उत्तरकाशी प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों का मुआयना कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया।

खास बात यह है कि स्थानीय लोगों द्वारा शुक्रवार को पानी के अंदर खड़े होकर किए गए प्रदर्शन के बाद ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया।

चेपड़ो बाजार में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल और 33 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चार गौशालाएं भी मलबे में दब गईं, जिनमें से एक में तीन गायों की मौत हो गई। थराली नगर पंचायत में पांच दुकानों को नुकसान पहुंचा है। थराली बाजार में 108 एंबुलेंस समेत कई छोटे.बड़े वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। रामलीला मैदान स्थित सरस्वती शिशु मंदिर भवन को भी भारी क्षति हुई है। राडीबगड़ में एसडीएम आवास सहित कई मकानों में मलबा घुस गया है। सबगड़ा गांव में नरेंद्र सिंह बिष्ट की पुत्री कविता (20) की मौत हो गई। डीडीआरएफ टीम ने पटवारी रोबट सिद्दकी के नेतृत्व में शव बरामद किया। चेपड़ो गांव के गंगा दत्त जोशी (78) अभी लापता हैं।

थराली आपदा का नुकसान एक नजर में

मृतक - कविता पुत्री नरेंद्र सिंह बिष्ट, उम्र 30 वर्ष, सबगड़ा

लापता - 1 गंगा दत्त जोशी, उम्र 78 वर्ष, चेपड़ो

घायल - 8 चेपड़ो गांव

दुकानें क्षतिग्रस्त- 33 चेपड़ो बाजार, थराली बाजार

गौशालाएं - 4 क्षतिग्रस्त, 3 गायों की मौत

वाहन क्षतिग्रस्त - दर्जनों, जिनमें 108 एंबुलेंस भी शामिल

सरकारी भवन प्रभावित - राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सरस्वती शिशु मंदिर भवन

मकान - कोटड़ीप, राडीबगड़ और सगवाड़ा क्षेत्र में कई मकानों में मलबा घुसा, एक मकान गिरा

प्रभावितों की सूची

घायल
देवी जोशी
गिरीश जोशी
कैलाश जोशी
हेमंत रावत
बलवंत सिंह
जसपाल सिंह
सुमित जोशी

अब 25 से 28 डिग्री तापमान में भी तैयार होगी मशरूम, वैज्ञानिकों ने शोध किया शुरू

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

हिमाचल. सोलन। अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही सर्द ही नही गर्म मौसम में भी मशरुम उगाया जा सकेगा। इसके लिए खुंब निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने शोध शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों ने अब 25 से 28 डिग्री तापमान में मशरूम को तैयार करने के लिए शोध शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द इसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद मशरूम तैयार करना पहले से आसान होगा।

इसका खुलासा हाल ही में निदेशालय में हुए वैज्ञानिकों के सेमिनार में खुंद निदेशालय के वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार ने किया था। डॉ. अनिल के अनुसार वैज्ञानिकों का शोध जारी है।

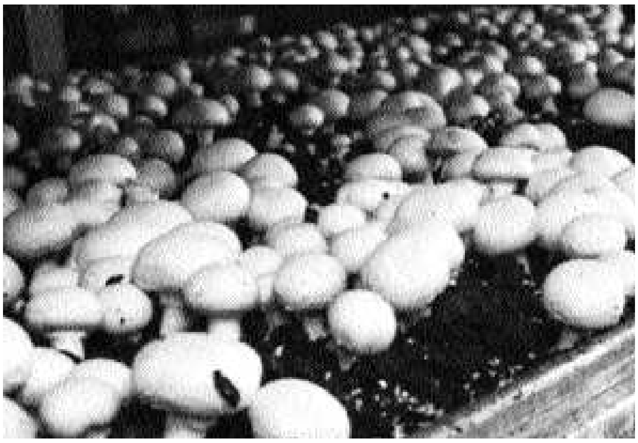

अभी तक तापमान को 16 से 18 डिग्री के बीच स्थिर रखने में दिक्कतें आती हैं। अधिक गर्म तापमान में मशरूम खराब हो जाती है। लिहाजा अधिक तापमान में मशरूम कैसे तैयार होगीए इसके लिए शोध शुरू कर दिया है। देशभर में ज्यादातर किसान अक्तूबर के बाद मशरूम की शुरुआत करते हैं और फरवरी तक बंद कर देते हैं। इसका कारण है कि इसी मौसम में तापमान कम रहता है। गर्मियों में नुकसान अधिक रहता है और वह मशरूम उत्पादन करना छोड़ देते हैं।

ठंडे क्षेत्रों में रहता है उपयुक्त

मशरूम उगाने के लिए अभी तक देशभर में केवल ठंडे क्षेत्रों में ही तापमान बेहतर होता है। जबकि गर्म क्षेत्रों में इसके तापमान को स्थिर रखना बड़ी चुनौती माना जाता है। क्योंकि वहां पर एसी और ब्लोर के सहारे ही तापमान को बनाया जाता है। गर इसमें कोई हल्की चूक हो जाए तो पूरी पैदावार खराब हो जाती है। अगर मशरूम उगाने के लिए 25 से 28 डिग्री तापमान पर शोध सफल हुआ तो यह खराब कम होगी और उत्पादकों को मुनाफा अधिक होगा।

मशरूम को अब 25 से 28 डिग्री तापमान में उगाने के लिए शोध जारी है। उम्मीद है कि जल्द इसमें सफलता मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो मशरूम उगाने का खर्चा कम होगा और उत्पादकों को इससे राहत मिलेगी। अभी तक मशरूम उगाने का सही तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच होता है। इससे अधिक तापमान में इसके खराब होने का डर बना रहता है।

डॉ. वीपी शर्मा, निदेशक खुंब निदेशालय सोलन

उप्र में 11 कीटनाशक पर लगाया प्रतिबंध

हलधर किसान, नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बासमती चावल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उसके अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाथरस समेत प्रदेश के 30 जिलों में 11 कीटनाशकों की बिक्री पर आगामी 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है। भारत का बासमती चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग रखता है, लेकिन कुछ कीटनाशकों के अवशेष पाए जाने पर निर्यात में दिक्कतें आती हैं। यही वजह है कि सरकार ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि इस सख्ती से चावल की गुणवत्ता बढ़ेगी और विदेशों में भारत का बासमती ब्रांड और मजबूत होगा।

इन जिलों में लागू हुआ प्रतिबंध

जिन 30 जिलों में यह रोक लगाई गई है, उनमें आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामलीए पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और संभल शामिल हैं।

किन.किन कीटनाशकों पर रोक

बासमती चावल में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों को बैन किया गया है, इनमें -

ट्राईसाइक्लाजोल, ब्यूप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइरीफस, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेडजिम, कार्बोफ्यूरान इनकी किसी भी प्रकार की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होगी। कार्रवाई का प्रावधान

जिला कृषि अधिकारी निखिल देव तिवारी ने बताया कि यदि किसी डीलर या विक्रेता द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री की जाती है, तो उसके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे बासमती चावल की खेती में जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। इसमें नीम ऑयल, ट्राईकोडरमा, ब्युवेरिया बेसियाना, स्यूडोमोनास, मैटाराइजियम, बीटी और एनपीवी को शामिल किया गया है। साथ ही कुछ वैकल्पिक उपायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

हर्बिसाइड बेचने वाली एचपीएम कंपनी का लाइसेंस निलंबित, तीन जिलों में एफआईआर दर्ज

हलधर किसान नई दिल्ली

घटिया और अमानक खाद व पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करते हुए लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने की है। राजस्थान सरकार ने एग्रोकेमिकल बनाने वाली इस कंपनी का उत्पादन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कंपनी के उत्पादों के उपयोग से मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा था। सैंपल जांच में उत्पाद की मिसब्रांडिंग की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया। यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर की गई है। राजस्थान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

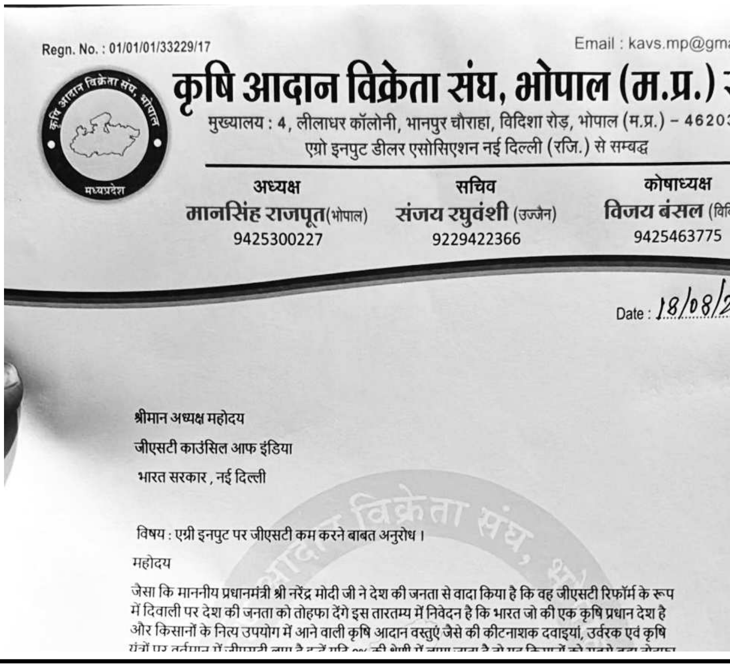

Regn. No. : 01/01/01/33229/17

Email : kavs.mp@gma

कृषि आदान विक्रेता संघ, भोपाल (म.प्र.)

मुख्यालय : 4, लीलाधर कॉलोनी, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.) – 4620

एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन नई दिल्ली (रजि.) से सम्बद्ध

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
मानसिंह राजपूत (भोपाल)	संजय रघुवंशी (उज्जैन)	विजय बंसल (वि
9425300227	9229422366	9425463775

Date : 18/08/2

श्रीमान अध्यक्ष महोदय

जीएसटी काउंसिल आफ इंडिया

भारत सरकार , नई दिल्ली

विषय : एग्री इनपुट पर जीएसटी कम करने बाबत अनुरोध ।

महोदय

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है कि वह जीएसटी रिफॉर्म के रूप में दिवाली पर देश की जनता को तोहफा देंगे इस तारतम्य में निवेदन है कि भारत जो की एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के नित्य उपयोग में आने वाली कृषि आदान वस्तुएं जैसे की कीटनाशक दवाइयां, उर्वरक एवं कृषि

द्वारा कंपनी को जारी पत्र में कहा गया है कि आपके उत्पाद के सैंपल की जांच में मिसब्रांडिंग पाई गई है। इसके चलते कंपनी की दोनों उत्पादन इकाइयों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अब कंपनी अगले आदेश तक अपने उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और वितरण नहीं कर सकेगी।

यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वॉरेंटाइन एंड स्टोरेज से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें कंपनी के उत्पाद क्लोरीमुरान इथाइल की मिसब्रांडिंग की पुष्टि हुई थी। कार्रवाई इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1968 की धारा 14 के तहत की गई है। साथ ही कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के कई किसानों से शिकायतें मिली थी कि क्लोरीमुरान इथाइल 25 प्रतिशत डब्ल्यूपी नामक खरपतवार नाशक के प्रयोग से किसानों की सोयाबीन फसलें खराब हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सैम्पल जब्त कर जांच की गई। नमूने घटिया पाए जाने पर मध्य प्रदेश के तीन जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई है और डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में जिन डीलरों ने यह खराब गुणवत्ता वाला हर्बिसाइड बेचा था, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। राजस्थान राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है।

नई फसल से पहले किसानों को बड़ा झटका

कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म

फाईल फोटो

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कपास की नई फसल बाजार में आने से एक माह पहले इसके आयात पर शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) को समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफसे 18 अगस्त की देर शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक 19 अगस्त से कपास का आयात बिना इंपोर्ट ड्यूटी के किया जा सकता है। कॉटन पर 10 फीसदी सीमा शुल्क लगता है और इसके ऊपर 10 फीसदी का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस मिलाकर प्रभावी ड्यूटी 11 फीसदी बैठती है, जो आज से समाप्त हो गई है।

सरकार के इस फैसले से आने वाले मार्केट सीजन में किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलने में मुश्किल खड़ी होने की आशंका बन गई है। वहीं कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई कपास की कीमतों में भी इस फैसले के चलते गिरावट आएगी। इस समय बाजार में सीसीआई 56000 से 57000 रुपये प्रति कैंडी (355.6 किलो) के दाम पर कॉटन बेच रहा है। वहीं आयातित कॉटन की कीमत 50 हजार रुपये से 51 हजार रुपये प्रति कैंडी रहने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक, करीब सप्ताह भर पहले तक टेक्सटाइल मंत्रालय के कुछ अधिकारी आयात शुल्क समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन हफ्ते भर में फैसला बदल गया और 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने आयात शुल्क समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि जो सीसीआई सरकार के लिए एमएसपी पर कपास की खरीद करता है और उसे बाजार में बेचता है, उसने भी कॉटन आयात पर शुल्क समाप्त करने पर सहमति जताई है।

अधिसूचना के मुताबिक, 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर, 2025 की अवधि के लिए आयात शुल्क समाप्त किया गया है। इस तरह 40 दिन की अवधि आयातकों को दी गई है। उद्योग सूत्रों का कहना है कि इस छोटी अवधि में केवल वही कॉटन आयात हो सकेगा जो या तो ट्रांजिट में है या फिर उन आयातकों को होगा जिनका माल कस्टम क्लीयरेंस के लिए गोदामों में रखा हुआ है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसे कॉटन की मात्रा करीब छह लाख गांठ (एक लाख टन) है। इस आयात की स्थिति में सरकार को करीब 170 करोड़ रुपये के आयात शुल्क का घाटा होगा। वहीं सीसीआई के पास बकाया स्टॉक को देखते हुए कीमतों में करीब पांच हजार रुपये की गिरावट के चलते उसका घाटा 700 करोड़ रुपये तक हो सकता है, क्योंकि आयातित कॉटन की कीमत करीब 51 हजार रुपये कैंडी रहने का अनुमान है।

वहीं कीमतों में इस गिरावट का असर आने वाले सीजन के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि बाजार की शुरुआत कम दाम पर होगी। आगामी मार्केटिंग सीजन के लिए सरकार द्वारा तय एमएसपी पर खरीदी गई कॉटन की लागत सीसीआई के लिए करीब 61 हजार रुपये प्रति कैंडी पड़ेगी। वहीं जिन घरेलू ट्रेडर्स के पास माल बकाया है उनको भी कीमत में कमी का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह नुकसान करीब 100 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस स्थिति में कॉटन पर सीमा शुल्क समाप्त करने का फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होने वाला है जो भारत को कॉटन का निर्यात करेंगी। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा काटन निर्यातक है और अब भारतीय बाजार में अमेरिकी काटन की बाढ़ आएगी, जिससे घरेलू कीमतें और गिरेंगी। कपास की खेती में आ रही लगातार कमी कपास की खेती में लगातार कमी आ रही है।

निर्णय का असर

केंद्र सरकार ने कपास पर लागू 11 फीसदी आयात शुल्क को हटाने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) चारुनी ने कड़ा विरोध करते हुए इस फैसले को कपास किसानों की आजीविका पर सीधा हमला बताया है।

किसानों के बीच आक्रोश, कपास की कीमतों में कटौती

बीकेयू चारुनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी के अनुसार, इस फैसले से देशभर के किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस एलान के मात्र दो दिनों के अंदर भारतीय कपास निगम ने कपास की कीमतों में 1100 रुपये प्रति कैंडी की कटौती कर दी है। इस तरह यह साबित होता है कि सरकार का यह कदम घरेलू बाजार के लिए कितना विनाशकारी है।

अमेरिकी कपास की आएगी बाढ़, घरेलू कीमतें लुढ़केंगी

बीकेयू चारुनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह फैसला कपडा उद्योग को लाभ पहुंचाने और भारत के दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक देश अमेरिका के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिकी कपास की बाढ़ भारतीय बाजारों में आएगी, जिससे कपास की घरेलू कीमतें और गिरेंगी। इस नीति का बोझ सीधे देश के किसानों पर पड़ेगा।

घटता उत्पादन, बढ़ता आयात

बीकेयू ने केंद्र के इस कदम से आगामी जोखिमों पर अपनी बात सामने रखी है। देश में कपास की खेती पहले से ही लगातार गिरावट झेल रही है। बीकेयू ने कहा कि 2024.25 में कपास के आयात में 107 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि उत्पादन 3.9 करोड़ गांठों से घटकर 3 करोड़ गांठ रह गया। चालू खरीफसीजन में बुवाई का रकबा भी 3.24 लाख हेक्टेयर है, जो बीते साल से 2.91 फीसदी कम है। बीकेयू के चारुनी ने आगे कहा कि ऊंची कीमतों पर कपास का स्टॉक करने वाले व्यापारी समेत किसान अब बर्बादी का सामना कर रहे हैं और आगामी फसल की कीमतों पर भी दबाव बना रहने की आशंका है।

बीकेयू चारुनी की केंद्र सरकार से चार मांगें

बीकेयू चारुनी ने कपास से जुड़ी चार मांग सरकार के सामने रखी हैं। इन मांगों में कपास पर आयात शुल्क की जल्द से जल्द बहालीए कपास पर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू करना, ऊंची कीमतों पर कपास खरीदने वाले किसानों और व्यापारियों को मुआवजा, बेहतर बीज आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं और सहायता तंत्रों के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति शामिल है।

आयात शुल्क हटने से क्या होगा?

सरकार किसी भी घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए अगर विदेशी आलू का भाव परिवहन खर्च समेत 30 रुपये प्रति किलो है। वहीं, घरेलू किसानों द्वारा उगाए गए आलू का भाव 110 रुपये हैं, तो ऐसे में सरकार विदेश आलू के आयात पर शुल्क लागू कर उसे महंगा करती है, जिससे आलू का आयात कम आकर्षक हो जाता है। इसी तरह कपास पर लागू 11 फीसदी आयात शुल्क हटने से विदेशी कपास का आयात सस्ता हो सकता है। वहीं, मिलें कपास के लिए विदेश बाजार की ओर रुख कर सकती हैं।

ट्रंप का टैरिफजिम्मेदार

दरअसल, इस पूरे मामले की तह में ट्रंप का टैरिफ जिम्मेदार है जिसने भारत सरकार और यहां के किसानों को सोचने पर मजबूर किया हैण् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में एकतरफा फैसला लेते हुए भारत पर 25 परसेंट का आयात शुल्क लगा दिया। साथ में 25 परसेंट की ड्यूटी और जोड़ दी।

इस बीच, भारत ने कपास के आयात को जीरो ड्यूटी के साथ आयात की इजाजत दे दी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को होगा जहां से बड़ी मात्रा में कपास भारत मंगाया जाता है।

केरल के कुट्टनाड में मछली पालन को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र पायलट परियोजना शुरू करेगा

हलधर किसान

कोच्चि। केरल के कुट्टनाड में मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। कोच्चि स्थित आईसीएआर.केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

इस नई पहल के अंतर्गत भारत सरकार का मत्स्य विभागए कुट्टनाड में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक और पारंपरिक जलीय कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इनमें एकीकृत मत्स्य पालन, पिंजरे में मछली पालन, सतत् एक मछली एक धान पहल और बायोफ्लोक मत्स्य पालन शामिल हैं।

इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा।

मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों की आजीविका बढ़ाना इस पहल का प्रथम लक्ष्य है।

पायलट परियोजना के अंतर्गत किसानों को जलीय कृषि और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों में जरूरी कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह परियोजना स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी जो फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, सफाई, पैकिंग और मछली व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और उपज का मूल्यवर्धन होगा। कुट्टनाड के विविध जलीय वातावरण को देखते हुए इस परियोजना को मीठे और खारे पानी की खेती की अलग.अलग पहलों में विभाजित किया जाएगा जो विशेष रूप से ऊपरी और निचले कुट्टनाड की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय एजेंसियों और कृषि विज्ञान केंद्रों सहित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस पहल के तुरंत और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाएगी जिससे कुट्टनाड क्षेत्र को महत्वपूर्ण और स्थायी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मत्स्य विकास आयुक्त डॉ. मोहम्मद कोया, सीएमएफआरआई के निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज और सीएमएफआरआई की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. इमेल्डा जोसेफने भी अपने विचार रखे जबकि विभिन्न शोध संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और केवीके के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

अतिवृष्टि से अतिवृष्टि से झारखंड में 2.18 लाख हेक्टेयर फसल खराबी का अनुमान

हलधर किसान. रांची

झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक ओर जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका असर खरीफ फसल पर पड़ा है। राज्य में औसतन 33 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है।

इस वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों की मानें तो राज्य में करीब 2.18 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। हालांकि अभी नुकसान होने का सर्वे जारी है।

राज्य में 31 अगस्त तक धान रोपनी की अंतिम तिथि है। ऐसे में अभी जिलों में फसलों के नुकसान होने का सटीक आंकड़ा आना बाकी है। जिसे राज्य के आपदा विभाग को भेजा जाएगा। फिर किसानों को राहत राशि देने पर फैसला लिया जाएगा।

राज्य में इस वर्ष खरीफफसल के लिए लगभग 30 लाख हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार यह आंकड़ा 28 लाख हेक्टेयर था। इस बार अच्छी बारिश के पूर्वानुमान को लेकर विभाग ने 30 लाख हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी के अनुरूप किसानों को बीज, खाद सहित अन्य साधन भी उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन अतिवृष्टि की वजह से धान के अलावा कई अन्य खरीफ फसल सहित सब्जियां भी बर्बाद हो रही है।राज्य में धान की खेती प्रमुख है।

विभाग की ओर से भी लगभग 18 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कुल खेती का लगभग 66 प्रतिशत है। इसका सबसे बड़ा कारण मौसम पर निर्भरता है, क्योंकि झारखंड में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। इसलिए किसानों की खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर करती है।

जानकारी के अनुसार राज्य में बारिश की वजह से मक्का की खेती 35 प्रतिशत प्रभावित हुई है। उसी तरह दलहन, और तिलहन की खेती 50 प्रतिशत प्रभावित हुई है।

शिलांग में सबसे साफ हवा, सबसे प्रदूषित शहर नंदेसरी

हलधर किसान नई दिल्ली

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 30 अगस्त 2025 को जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि देश के जहां 55 फीसदी शहरों में हवा साफ है। वहीं 40 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 4.4 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज हवा साफ है।

आंकड़ों में देखा जाए तो शिलांग की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 10 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर नंदेसरी की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 27 गुणा खराब है।

गौरतलब है कि कल अगरतला में प्रदूषण से स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 331 तक पहुंच गया। हालांकि कल से अगरतला की वायु गुणवत्ता में 305 अंकों का भारी सुधार आया है। इसके साथ ही वहां एक्यूआई सुधरकर 26 पर पहुंच गया। वहां एक ही दिन में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से साफहो गई है।

प्रदूषण के मामले में आज मेघालय का बर्नीहाट दूसरे स्थान पर है, जहां एक्यूआई 140 दर्ज किया गया। इसी तरह कांचीपुरम 129 अंकों के साथ प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर है। एलूर में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 125 अंकों के साथ आज चौथे स्थान पर है। वहीं बद्दी (119) पांचवें जबकि छपरा (114) छठे स्थान पर है। इसी तरह आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में समस्तीपुर (108), गुम्मिडिपूंडी (105), जैसलमेर (104) और रूपनगर (104) भी शामिल हैं।

रुझानों से पता चला है कि इस दौरान जहां नंदेसरी, बर्नीहाट आदि में प्रदूषण के महीन कण पीएम 2.5 हावी रहे। वहीं कांचीपुरम, बद्दी, समस्तीपुर, गुम्मिडिपूंडी, जैसलमेर आदि की हवा में पीएम10 से स्थिति चिंताजनक थी। वहीं कुछ शहरों में जहां कार्बन हावी था, वहीं कुछ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से स्थिति खराब रही। राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार तीसरे दिन प्रदूषण में गिरावट आई है, जिसके साथ ही वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधरकर 72 पर पहुंच गया है।

दिल्ली की तरह ही आज देश के छोटे.बड़े 90 शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक दर्ज की गई। इन शहरों में हैदराबाद, जयपुर, जलना, जालौर, झांसी, झुंझुनूं, जोधपुर, जोरापोखर, कानपुर, करौली, करूर, कटिहार, क्योंझर, किशनगंज, कोहिमा, कोटा, लखनऊ, लुधियाना, मालेगांव, मंडी गोबिंदगढ़, मंडीदीप, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, नगांव, नागपुर, नलबाड़ी, नांदेड़, नोएडा, पाली, पटना, पिंपरी.चिंचवाड, पीथमपुर, पुणे, राजमहेंद्रवरम शामिल थे। देश में संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में पांच फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 223 में से 123 शहरों में हवा बेहतर (0.50 के बीच) है। 90 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक (51.100 के बीच) रिकॉर्ड किया गया, गौरतलब है कि 29 अगस्त 2025 को यह आंकड़ा 95 दर्ज किया गया था। 9 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम (101.200 के बीच) बनी हुई है। दूसरे शहरों की तुलना में नंदेसरी (285) में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां एक्यूआई 300 के करीब पहुंच गया। कल अगरतला में वायु गुणवत्ता सूचकांक 331 रिकॉर्ड किया गया।

इन शहरों में साफ हवा

आज देश में अमृतसर सहित 123 शहरों में हवा साफरही। इन शहरों में देहरादून, डिंडीगुल, डूंगरपुर, फिरोजाबाद, गंगटोक, गया, गोरखपुर, गुरूग्राम, गुवाहाटी, हल्दिया, हापुड, हावड़ा, इंदौर, जबलपुर, जालंधर, जलगांव, झालावाड़, कलबुर्गी, कारवार, काशीपुर, कटनी, खन्ना, खुर्जा, कोल्हापुर, कोलकाता, कोप्पल, कुंजेमुरा, लातूर, मदुरै, महाड, मंगलौर, मंगुराहा, मेरठ, मिलुपारा, मीरा.भायंदर, मोतिहारी, मुंबई, मुंगेर, मैसूर, नागपट्टिनम, नागौर आदि शामिल थे।

चीन से सौदे के बाद भारतीय आयातकों ने रोकी सोया तेल खरीदी

अर्जेंटीना के कीमतें घटाने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी

नई दिल्ली। भारतीय आयातकों ने बीते महीने चीन से 1.5 लाख टन सोयाबीन तेल खरीदने का सौदा किया था। लेकिन, अब उन्होंने चीन से खरीदारी रोक दी है। अर्जेंटीना द्वारा कीमतों में कटौती के बाद भारतीय खरीदारों ने यह फैसला लिया। बता दें कि अर्जेंटीना भारत के कुल सोयाबीन तेल आयात का 65 फीसदी हिस्से की सप्लाई करता है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया किए भारतीय खरीदारों ने चीन से सौदे तब किए जब कीमतें मौजूदा स्तर पर थीं। लेकिन अर्जेंटीना ने कीमतें घटाकर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, मुंबई में डीगम्ड सोयाबीन तेल की लैंडेड कीमत 1,205 डॉलर प्रति टन है, जो पिछले साल से 18.5 फीसदी अधिक है। वहीं, आरबीडी पाम तेल की कीमत 1,105 डॉलर प्रति टन है।

पतंजलि फूड्स, अडानी विल्मर और कारगिल, बंज जैसी कंपनियों ने सितंबर.दिसंबर 2025 के लिए चीन से सौदे किए थे। लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता के अनुसार, भारतीय खरीदार अब वियतनाम जैसे देशों से तेल मंगवाने में स्मार्ट हो गए हैंए जहां शिपमेंट में केवल 10 दिन लगते हैं, जबकि अर्जेंटीना से 45.60 दिन।

नेपाल और अमेरिका से बढ़ता आयात

नेपाल साफ्टा समझौते के तहत भारत को रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों का तेल निर्यात कर रहा है। नवंबर 2024 से जून 2025 तक नेपाल से 5.2 लाख टन तेल आयात हुआ, जिसमें 4.03 लाख टन सोयाबीन तेल था। दूसरी ओर अमेरिका ने 2024 में 4.6 लाख टन सोयाबीन तेल निर्यात किया, जिसमें भारत का हिस्सा 20 प्रतिशत था। बायोफ्यूल मांग के चलते अमेरिका में नए क्रशिंग प्लांट स्थापित हो रहे हैं।

क्या फिर लौटेगा चीन की ओर रुख?

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीएन पाठक ने कहा कि अगर चीनी कीमतें अर्जेंटीना के बराबर हुईं, तो भारत फिर से चीन की ओर रुख कर सकता है, क्योंकि वहां से शिपमेंट में केवल तीन सप्ताह लगते हैं। बाजार के रुझानों के आधार पर भारतीय खरीदारों की रणनीति में बदलाव संभव है।

वियतनाम और नेपाल बन रहे नए स्रोत

वियतनाम में ठनदहम कंपनी का क्रशिंग प्लांट है, जहां से तेल निकालकर भारत भेजा जाता है। नेपाल भी भारत को सस्ता रिफाइंड सोया ऑयल, सूरजमुखी और रेपसीड ऑयल साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत निर्यात कर रहा है।

भारत अमेरिका से भी कर रहा है आयात

2024 में अमेरिका ने 4.6 लाख टन सोया ऑयल एक्सपोर्ट कियाए जिसमें 20प्रतिशत हिस्सा भारत ने खरीदा। एसईए के अनुसार, नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच भारत ने अमेरिका से 1.88 लाख टन सोया ऑयल मंगवाया।

भविष्य में चीन से फिर हो सकती है खरीद

अगर चीन अपनी कीमतें फिर से कम करता है और सप्लाई समय पर देता है, तो भारतीय आयातक दोबारा चीन की ओर रुख कर सकते हैं। फिलहाल, भारत सस्ते और जल्दी मिलने वाले विकल्पों पर ध्यान दे रहा है। तेल की कीमतें और डिलीवरी टाइम भारतीय कंपनियों के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। स्मार्ट खरीदारी के जरिए भारत अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है और लगातार बदलते मार्केट पर पैनी नजर बनाए हुए है।

डिलीवरी में समय का फर्क

अर्जेंटीना से तेल आने में 6 हफ्ते (45.60 दिन) लगते हैं, जबकि वियतनाम और चीन से यह डिलीवरी 10 से 21 दिनों में हो जाती है। ऐसे में अगर चीन फिर से अर्जेंटीना जैसी कीमतें देता है, तो भारतीय कंपनियां वहां से खरीद शुरू कर सकती हैं।

.. इधर इंडोनेशिया से मिला भारत को झटका, रुका मूंगफली निर्यात

भारत से मूंगफली निर्यात करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी ने 27 अगस्त 2025 से भारत से मूंगफूली के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय अचानक नहीं बल्कि गुणवत्ता से जुड़े गंभीर मुद्दों के बाद लिया गया है।

रोक का कारण

भारत से भेजी गई कुछ मूंगफली की खेपों में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं पाया गया। इंडोनेशियन अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला नॉन.कम्प्लायंस का है, यानी निर्यात के दौरान जरूरी क्वालिटी चेक और सुरक्षा मानकों का ठीक से पालन नहीं हुआ। चूंकि मूंगफली सीधा खाने योग्य उत्पाद है और इसे स्नैक्स, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंडोनेशिया ने तुरंत यह कदम उठाया ताकि स्थानीय उपभोक्ताओं की सेहत पर कोई असर न पड़े।

मौजदा शिपमेंटस का क्या होगा?

यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है। नोटिस जारी होने की तारीख से अगले 7 दिनों के भीतर भेजे गए शिपमेंट्स को इंडोनेशिया में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इन खेपों की कड़ी जांच और री.टेस्टिंग होगी। अगर किसी शिपमेंट में मानकों की कमी पाई गई तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर वापस भेज दिया जाएगा।

भारतीय निर्यातकों पर असर

भारत दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देशों में से एक है और इसका बड़ा हिस्सा निर्यात होता है। इंडोनेशिया भारतीय मूंगफली के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। ऐसे में इस रोक का सीधा असर निर्यातकों और किसानों दोनों पर पड़ेगा। जिन किसानों ने अपनी फसल निर्यात के लिए बेची है, उनके दामों पर असर पड़ सकता है। अगर मांग घटती है, तो बाजार में कीमतें नीचे आ सकती हैं।

जीएसटी काउंसिल आफ इंडिया से एग्री इनपुट पर जीएसटी कम करने की उठी मांग

हलधर किसान इंदौर.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपावली पर जीएसटी रिफॉम करने की घोषणा के बाद आमजन के साथ व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों को नई उम्मीद बंधी है।

मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत एवं सचिव संजय रघुवंशी ने जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर मांग की है कि कृषि आदान वस्तुएं जैसे की कीटनाशक दवाइयां, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों पर वर्तमान में जीएसटी लागू है, इन्हें यदि 0 प्रतिशत की श्रेणी में लाया जाता है तो यह किसानों को सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है।

श्री रघुवंशी ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्तमान में उर्वरकों पर 5: जीएसटी लिया जा रहा है एक तरफ तो यूरिया एवं डीएपी पर प्रति बैग 1500 से 2000 की सब्सिडी दी जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं उत्पादों पर 12 रुपए से लगाकर 65 रुपए तक की 5 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए उर्वरकों को शून्य प्रतिशत की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है यदि उसे 0 या 5 प्रतिशत किया जाता है तो यह किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि कीटनाशक दवाइयां सिर्फ और सिर्फ किसानों के ही प्रयोग में आती है ।

इसी प्रकार कृषि यंत्रों को भी जीरो प्रतिशत या 5प्रतिशत की श्रेणी में लाया जाए तो किसानों को फायदा हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में समस्त कृषि आदानों को 5 प्रतिशत या उससे कम करने पर गंभीरता से विचार करें। एवं मोदी जी ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा देने का जो वादा किया गया है उसे पूरा करें ।

संघ ने आशा व्यक्त की है कि जीएसटी सदस्यगण इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए देश में कृषि आदानों (एग्री इनपुट) को 0 और 5 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी के श्रेणी में नहीं रखेंगे ।

कृषि उपकरणों पर जीएसटी

फलों, अनाजों, सूखी फलीदार सब्जियों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई और ग्रेडिंग के लिए आने वाली मशीनों पर सरकार 18 फीसदी जीएसटी लेती है। बीजों और कीटनाशक की खरीद पर भी 18 फीसदी ही जीएसटी लगता है।

कृषि मशीनरी, हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीनरी, घास काटने की मशीन, यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त अंकुरण संयंत्र सहित अन्य कृषि मशीनरी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। ट्रैक्टर पर भी जीएसटी लगता है।

एग्रो केमिकल पर इतना जीएसटी क्यों?

फर्टिलाइजर पर जीएसटी 5 फीसदी है, जबकि एग्रो केमिकल पर 18 परसेंट। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कीटनाशकों पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की वजह से ज्यादातर किसान बिल पर खरीद नहीं करते, ऐसे में सरकार को टैक्स का नुकसान होता है और नकली पेस्टिसाइड मिलने का खतरा बढ़ जाता है।

बाजार खोलो या अनैतिक टैरिफ झेलो ?

अमेरिका का मित्रता का वह स्वर, जो हमेशा शिष्टाचार की बात करता था, अब वैश्विक पूंजी के गणित में विचित्र बेसुरा व असंवेदनशील हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त 2025 से भारत पर अचानक 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने मित्रता को व्यापारिक तानाशाही के रूप में परिभाषित कर दिया। भारत, जहां 700 मिलियन से अधिक लोग सीधे सीधे जिस कृषि.आश्रित व्यवस्था से रोटी, रोजी रोजगार के लिए पूरी तरह आश्रित हैं तथा 140 करोड़ लोगों की भोजन की थाली जिस पर पूरी तरह निर्भर है, इसके लिए यह झटका केवल आर्थिक नहीं, आत्म.सम्मान का प्रश्न भी है।

बहाना ऊंचे टैरिफ, रूस से सैन्य संबंध या कुछ और हो, असल मुद्दा यही है। भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी जीए फसलों, जीएम उत्पादों और मीट मिल्क, सब्सिडी वाले डेयरी उत्पादों के लिए खोलना। क्या यही है स्वतंत्र व्यापार, क्या यह वही ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें किसानों की सदियों पुरानी मेहनत को सस्ते विदेशी उत्पादों से कुचलना जायज़ है? हमारे उत्पादन की मिट्टी की सुगंध, हमारे सामूहिक प्रयास, हमारी खेती की मूल संस्कृति की कीमत क्या अमेरिकी व्यापारी राष्ट्रपति समझेंगे?

700 मिलियन खेती पर आश्रित लोग सिर्फआंकड़ा नहीं, एक संघर्षशील विरासत हैं। भारतीय सहकारिता आंदोलन ने न केवल देश में दूध की नदियां बहायीं, बल्कि छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। अमेरिकी डेयरी उद्योग के सब्सिडी.धंधों का एकाधिकार हमारे किसानों का पूर्ण संहार होगा।

अब वक्त है, जब भारत सरकार को अमेरिकी दबावों का शिकार बनने के बजाय, आत्मनिर्भर स्वाभिमान के साथ नाश् कहना चाहिए। रूस के साथ हमारे समन्वय पर तथा लगाए जा रहे अन्य आरोप सिर्फबहाना हैं। सरकार को खाद्य सुरक्षा, कृषि नीति और किसानों के अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी दबाव या लालच के आगे झुकना उचित नहीं।

वास्तविक आंकड़े और 25 प्रतिशत टैरिफका प्रभाव

भारत का कुल विदेश व्यापार=-1.3 ट्रिलियन (करीब 108 लाख करोड़ रु) भारत.अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार- 150 अरब (करीब 5 लाख करोड़ रु)

भारत से अमेरिका को कृषि.आधारित निर्यात- 15 अरब ;करीब 27 लाख करोड़ रुण्द्ध

25: टैरिफका अनुमानित असर- 3.75 अरब (करीब 31 हजार करोड़ रु) की अतिरिक्त लागत।

निर्यात में संभावित गिरावट- 20-30 प्रतिशत (यानी 4.5 अरब/37,000 करोड़ रु तक की हानि)

जीडीपी पर प्रभाव- 3-0.5 प्रतिशत (60,000-1,00,000 करोड़ रु का असर)

विदेशी व्यापार में संभावित गिरावट- 5-2 प्रतिशत (20,000/25,000 करोड़ रु)

इस बार 10 दिन के होंगे नवरात्र, गज पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

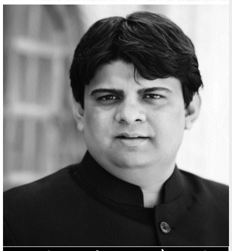

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन अजमेर

शक्ति के 9 रुपों की की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरु होने जा रहे है। इस बार नवरात्र की विशेषता यह रहेगी कि भक्तों को माता के नौ दिन नही बल्कि 10 दिन सेवा का अवसर मिलने वाला है।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) अजमेर के अनुसार माता गज पर सवार होकर आएंगी। इस बार मां दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर और एक अक्तूबर को नवमी, जबकि चतुर्थी तिथि दो दिन होने के चलते नौ के बजाय 10 दिनों तक शक्ति की आराधना भक्त करेंगे।

नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को और महानवमी एक अक्तूबर को मनाई जाएगी। दो अक्तूबर को माता को विदाई दी जाएगी। ज्योतिषाचार्य श्री सोनी ने बताया कि शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिनों का होगा

घटस्थापना मुहूर्त

अमृत मुहूर्तः सुबह 6.19 बजे से 7.49 बजे तक

शुभ मुहूर्त - सुबह 9.14 बजे से 10.49 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11.55 से 12.43 बजे तक रहेगा। मां दुर्गा का आगमन सोमवार के दिन हो रहा है, तो इस बार उनका वाहन हाथी है। मान्यता के अनुसार मां हाथी पर आती हैं, जो सुख.समृद्धि और शांति का प्रतीक है।

और 11वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा।

प्रतिपदा की शुरुआत भोर में 1. 25 बजे होगी और अगले दिन मध्यरात्रि के बाद 2. 57 बजे तक रहेगी। चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर को रहेगी। दो दिन चतुर्थी

शारदीय नवरात्रि तिथि

22 सितंबर - प्रतिपदा तिथि
23 सितंबर - द्वितीय तिथि
24 सितंबर - तृतीया तिथि
25 सितंबर - चतुर्थी तिथि
26 सितंबर - चतुर्थी तिथि
27 सितंबर - पंचमी तिथि
28 सितंबर - षष्ठी तिथि
29 सितंबर - सप्तमी तिथि
30 सितंबर - अष्टमी तिथि
01 अक्तूबर - नवमी तिथि
02 अक्तूबर - दशहरा

तिथि का मान रहेगा और मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांड का पूजन होगा। इस बार माता का आगमन गज पर होगा और प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर होगा। इस बार नवरात्र का योग देश और दुनिया के लिए सुख दायक है। इसके साथ ही शक्ति की आराधना का यह पर्व राष्ट्र के लिए उन्नति सूचक है। देश की संप्रभुता एवं प्रभाव बढ़ेगा। माता का गज पर आगमन और कंधे पर प्रस्थान दोनों स्थितियां शुभदायक हैं। नवरात्र में तिथि की बढ़ोतरी अच्छी मानी जाती है। देश का व्यापार बढ़ेगा, पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे और यह शुभ फलदायक है। ये संकेत है कि आने वाला समय सुख, समृद्धि से परिपूर्ण होगा।

प्रतिपदा पर हस्त नक्षत्र में होगी घटस्थापना

शारदीय नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर होगी। इस दिन सुबह से ही हस्त नक्षत्र लग रहा है। इस दौरान कलश स्थापना बहुत शुभकारी मानी जाती है। इसके साथ इस दिन पूरे दिन शुक्ल योग भी मिल रहा है।

वर्ग पहेली नं. 14

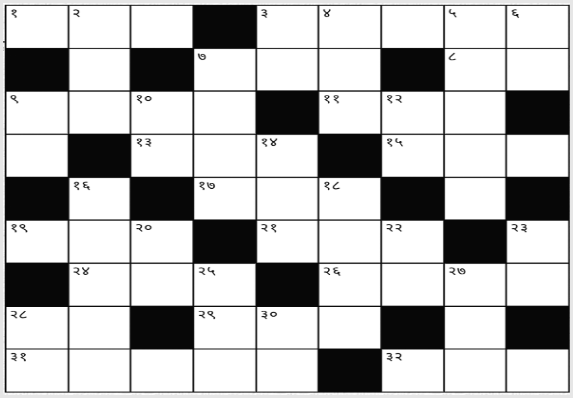

बाएं से दाएं

1. आश्चर्य, अचरज (3)
3. सर्वनाश, बरबाद (5)
7. सोना, स्वर्ण (3)
8. शोर (2)
9. कृष्णपक्ष की अंतिम रात (4)
11. असहाय (3)
13. हंस की जाति का एक जल पक्षी (3)
15. रद्दी का व्यापारी (3)
17. वैधानिक सम्बन्ध, विच्छेद (3)
19. पतंगा (3)
21. गला (3)
24. तमिलनाडु की राजधानी का पुराना नाम (3)
26. कलाबाजी, कौशल, बाजीगरी (4)
28. हाथी पर बैठने के लिए लगाया जाने वाला पीढ़ा (2)
29. महिमा, महानता, महत्व (3)
31. जनता का मुखिया (5)
32. विपत्ति, संकट (3)

ऊपर से नीचे.

2. शशि, इंदु (3)
3. दिल, अंत: करण (2)
4. टीका, बड़ी बिन्दी (3)
5. कृपालु, दयालु (5)
6. टहूका, ठोकर (2)
7. व्यायाम (4)
9. ठहरने का स्थान (2)
10. चरबी, मज्जा (2)
11. दृश्य, शोभा, छवि (2)
12. कुम्हार का औजार (2)
14. मशवरा, राय (3)
16. लेखा बही, आदि रखने की पेटी (5)
18. प. बंगाल की राजधानी का पुराना नाम (4)
20. अनिष्टकारी समय (2)
22. हाथ, टैक्स, समय (2)
23 बहुत, ज्यादा (2)
25. वक्त (3)
27. छटपटाहट(3)
28. पानी की बड़ी नांद (2)
30. अधिकार (2)

वर्ग पहेली नंबर 13 का हल

म	शा	ल	■	गो	द	भ	र	ना
हा	■	व	सू	ली	■	■	ख	■
व	रु	ण	■	बा	ल	■	र	■
र	■	■	डो	री	■	बु	खा	री
■	पि	छ	ड़ा	■	दु	रा	व	■
उ	ल	टा	■	स्व	र्ग	■	■	प
■	प	■	सा	यं	■	सु	रं	ग
■	ड़	■	■	व	सु	धा	■	ला
ना	ना	प्र	का	र	■	र	सि	या

बीज कानून पाठशालाः आरबी सिंह, बीज कानून रत्न की कलम से..

बीज की एमआरपी..

हलधर किसान इंदौर

बीज कृषि का अनमोल रत्न है। इसकी गुणवत्ता के लिये बीज अधिनियम.1966, बीज नियम.1968, बीज नियन्त्रण आदेश.1983 जिसकी रचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से हुई है लागू है। बीज की गुणवत्ता एवं बीज विक्रय का नियमन इन कानूनों के द्वारा किया जाता है। इन इन कानूनों की पालना करवाने के लिये बीज निरीक्षक और बीज लाइसेंसिंग प्राधिकारी को असीम शक्तियां दी हुई हैं।

कृषक को बीज उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में सुगमता से उसकी पहुंच तक पहुंच सके इसके लिये वाट एवं नापतौल अधिनियम.1976 एवं नियम 1977 लागू है जो अब विधिक माप विज्ञान ;पैक की गई वस्तुएंद्ध नियम.2011 कहलाते हैं और बीज के पात्र पर एमआरपी या यूएसपी या विधिक माप विज्ञान अधिनियम.2009 या नियम.2011 का उलंघन होने पर विधिक माप विज्ञान निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अपार शक्तियां दी हैं और यदाकदा बीज पैकेटों पर भी विधिक माप विज्ञान के प्रावधानों का उलंघन होने पर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करता है।

1- एमआरपी

बीज के पात्रों पर भी एमआरपी लिखी जाए। दिनांक 01 अप्रैल 2022 से एमआरपी के साथ यूनिट सेल प्राईज यूएसपी भी लिखना आवश्यक कर दिया है। एक किलों से नीचे मूल्य प्रति ग्राम और किलो से उपर की पैकिंग पर यूएसपी प्रति किलो अंकित की जाए। बिना एमआरपी लिखे विधिक माप विज्ञान नियम 2011 का उल्लंघन है और उल्लंघन होने पर दण्ड 20,000 रुपये है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि दण्ड को कम्पाउन्ड (समझोता) कर दिया जाता है और यदि आरोपी एक मुश्त भुगतान कर देता है तो वह आरोप से मुक्त हो जाता है और उस पर कोई अभियोजन / मुकद्मा/वाद दायर नहीं होता है। वह 8.10 साल न्यायालयों की आवाजाही से बच जाता है। यदि एक साथ जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो व्यापारी पर मुकद्मा दायर किया जाता है।

-एमआरपी क्या हो ?

किसी बीज का एमआरपी क्या हो ? यह बीज उत्पादक कम्पनी की उत्पादन लागत डीलर कमीशन मुनाफा, की गणना कर निश्चित की जाती है। बीज उत्पादन तकनीकि साधारण या संकर। संकर उत्पादन प्रणाली में जीएमएस या मासक्यूलेशन है। बीज की एमएसपी या यूएसपी कितनी हो यह बीज उत्पादक का एक मात्र अधिकार है। एमआरपी के लिये बीज उत्पादक पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। जब तक की फसल का अधिकतम मूल्य किसी अधिनियम/ कानून द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न किया गया हो। उदाहरण के लिये केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार बीटी कपास की विक्रय एमआरपी प्रति वर्ष तय होती है।

-एमआरपी और अभियोजन-.

एमआरपी के उलंघन के लिये विधिक माप विज्ञान निरीक्षक वाद दायर कर सकता है यदि दोषी व्यक्ति ब्वउचवनदकपदह के दौरान जुर्माना नहीं जमा करता। कृषि अधिकारी बीज निरीक्षक तथा लाइसैंस अनुज्ञापन प्राधिकारी को बीज अधिनियम.1966, बीज नियम.1968 तथा बीज नियन्त्रण आदेश.1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम.1955 के उलंघन करने पर वाद दायर करने का अधिकार है न कि विधिक माप विज्ञान ;पैक वस्तुद्ध नियम 2011 के उलंघन करने पर महाराष्ट्र कॉटन सीड्स या ऐसे ही अन्य राज्यों द्वारा बनाए अधिनियमों के तहत कपास (बीटी गैर बीटी) की विक्रय दर घोषित की गई हो जैसे बीटी कपास के लिये भारत सरकार हर वर्ष बीटी जीन 1 और बीटी जीन 2 में करती है, उसके विरूद्ध तो एमआरपी में कार्यवाही कर सकते हैं तथा अन्य फसलों में जिनकी दर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तय नहीं की गई के बारे बीज निरीक्षक द्वारा वाद दायर करना त्रुटि पूर्ण है। ***हर रिश्ते में कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता है किसान अच्छे उत्पादन हेतु प्रमाणित बीज बोता है।***

लेखक..
आर.बी सिंह, बीज कानून रत्न, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि. सम्प्रति कला निकेतन, ई.70, विधिका.11, जवाहर नगर, हिसार.125001 (हरियाणा), दूरभाष 79883.04770, 94667.46625

संकलन सहयोगी- संजय रघुवंशी, श्रीकृष्णा दुबे, कृषि आदान विक्रेता संघ

टैरिफ का असर, घटा कपास का भाव

हलधर किसान. नई दिल्ली। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने का साफ असर अब झलकने लगा है। पिछले 10 दिनों में तीन बार कपास का फ्लोर प्राइस घटाया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफइंडिया यानी ब्ब्(ने कपास का फ्लोर प्राइस 600 रुपये प्रति कैंडी (एक कैंडी में 356 किलो कपास) तक घटा दिया है। यहां जान लेना चाहिए कि कॉटन का फ्लोर प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की तरह ही होता है, लेकिन एमएसपी से तकनीकी मायने में यह थोड़ा अलग होता है। कॉटन का फ्लोर प्राइस घटाने का मामला सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल शून्य यानी खत्म कर दिया गया है। 30 अगस्त को पिछले 10 दिनों में तीसरी बार कपास का फ्लोर प्राइस घटाया गया है। व्यापारिक सूत्रों ने बताया कि सीसीआई दाम में गिरावट इसलिए कर रहा है, ताकि मिलों के लिए कपास के दाम को थोड़ा कम और आकर्षक बनाया जा सके। सीसीआई एक सरकारी संस्था है जो कपास से जुड़े मामलों को देखती है। सूत्रों का कहना है कि सीसीआई आने वाले समय में और भी दाम गिरा सकता है ताकि कपास के स्टॉक को मिलों के लायक सस्ता बनाया जा सके। इसके पीछे सीसीआई और सरकार की ये मंशा है कि मिल मालिक किसानों से डायरेक्ट सस्ते में कपास खरीदें और उन्हें आयातित कपास खरीदने की जरूरत न पड़े। इससे किसानों का कपास तो निकल जाएगा, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना होगा क्योंकि वे अधिक दाम की उम्मीद कर रहे हैं।

19 अगस्त के बाद तेज गिरावट

19 अगस्त को जब केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया, तब सीसीआई ने कपास के दाम में 600 रुपये प्रति कैंडी की गिरावट की। उसके अगले दिन 500 रुपये की गिरावट हुई। इस तरह पिछले 10 दिन में कपास के फ्लोर प्राइस में 1700 रुपये तक की गिरावट है।

प्रादेशिक सम्मेलन सम्मेलन में दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष कलंत्री का किया सम्मान

बिहार में एक मंच पर आए एग्रो इनपुट डीलर्स

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली की बिहार इकाई का प्रादेशिक सम्मेलन दरभंगा में आयोजित किया गया। प्रदेश संरक्षक एवं महासचिव अवधेश कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री एवं विशिष्ट अतिथि हरियाणा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरमेश सिंह का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर तथा मखाना की माला पहनाकर स्वागत किया गया।

बिहार प्रादेशिक अध्यक्ष एवं सिवान से पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह ने स्वागत संबोधन में कहा कि हमारा संगठन व्यापारी एकजुटता एवं किसान हित के प्रति प्रतिबद्ध है। ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कलंत्री ने संगठन के क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय संगठन के प्रयास से व्यापार करने में कई सहूलियतें मिली है। संगठन निरंतर कृषि व्यापार ओर व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। जिले सहित प्रदेश ओर राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को संगठन केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उनके निराकरण का प्रयास करता है। कई समस्याओं का निराकरण होने से व्यापारियों को राहत भी मिली और यही कारण है कि आज कृषि आदान विक्रेता संघ देश के हर जिले और ब्लॉक स्तर तक पहुंचा है। संगठन ी यह एकता हमें बनाए रखना है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सिंह ने आवाहन किया कि संगठन में ही शक्ति है। अगर व्यापारी एकजुट होते हैं तो समुचित अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। अगर किसी के द्वारा परेशान करने का प्रयास किया जाता है वह सफल नहीं होगा।

संचालन कर रहे प्रदेश कोषाध्यक्ष मनमोहन सरावगी ने आग्रह किया कि हम हमें तन-मन- धन से संगठन का सहयोग करना चाहिए। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए व्यापारियों ने भाग लिया तथा कृषि इनपुट व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज बरोलिया, अवधेश राजपाल उदय शंकर प्रसाद, पप्पू यादव आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं इस बात पर सहमति जताई कि संगठन किसानों तथा विक्रेताओं के हित में निरंतर कार्यरत रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु हर स्तर पर प्रयास करता रहेगा। उक्त जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कुमार रघुवंशी उज्जैन ने दी।

बैठक में इन बिंदुओं पर लिया निर्णय

संगठन एवं व्यापारियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप लॉन्च किया गया। ऐप के द्वारा विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं जरूरी दिशा-निर्देशों को ससमय पहुंचाया जाएगा। किसानों व विक्रेताओं के हितों की रक्षा हेतु कंपनियों द्वारा अनुचित टैगिंग व्यवस्था के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। खुदरा एवं थौक व्यापारियों में बेहतर तालमेल/ आपसी समन्वय एवं सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया।

डीलरों को यथोचित लाभ हेतु मार्जिन वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा की गई। खुदरा बिक्री केंद्रों तक उर्वरकों की भारत सरकार के आदेशानुसार सीधे एफओआर डिलीवरी किए जाने की मांग रखी गई।

नियम-कानून के नाम पर डीलरों को परेशान किए जाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। लाइसेंस निर्गमन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाए जाने पर बल दिया गया।

आगामी बुवाई के रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की ससमय निर्बाध आपूर्ति करने हेतु सरकार से मांग की गई। इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य विषयों पर भी विचार- विमर्श किया गया।

श्री दुबे की प्रतिक्रिया

जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कृषि आदान विक्रेता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी की सक्रियता का परिणाम है कि बिहार राज्य में बड़ी संख्या में व्यापारी एक मंच पर आए और संघ के बीच अपनी बात रखी एवं संघ को समर्थन देकर मजबूती प्रदान की। संगठन की यह एकता और मजबुती ऐसे ही बनी रहेगी तो व्यापारियों को बेवजह परेशान करने वाले पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे।

पंजाब में बाढ़ से 2.56 लाख लोग प्रभावित, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

हलधर किसान, नई दिल्ली

पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 1,000 से ज्यादा गांव और 61,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। बाढ़ से प्रभावित सबसे सबसे ज्यादा गांव गुरदासपुर जिले में हैं। बाढ़ के चलते पंजाब में भारी तबाही हुई है।

1 सितंबर सोमवार शाम तक 29 लोगों के मारे जाने और 2.56 लाख लोगों के प्रभावित होने की खबर है। हजारों एकड़ में लगी फसल खराब हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से लौटते ही पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। इस बीच, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने को लोगों से राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की।

सेना, सीमा सुरक्षा बल, और जिला अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से कुल 11,330 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई मंत्री और विधायक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। राज्य के जल संसाधन मंत्री गोयल ने पिछले 37 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

गोयल ने दावा किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा जून में समय पर पानी छोड़े जाने से तबाही काफी कम हो सकती थी।

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री एस. हरदीप सिंह मुंडियन के अनुसार, बाढ़ ने 12 जिलों में 2.56 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। जान.माल, कृषि और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 15,688 लोगों को निकाला गया है। राज्य सरकार ने 129 राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 7,144 लोग रह रहे हैं। बाढ़ से अब तक 1,044 गांव प्रभावित हुए हैं।

सेना, नौसेना और वायु सेना ने 10 टुकड़ियां तैनात की हैं। बाढ़ से पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। 94,061 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिन नं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 98262 25025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)